Self-Sufficiency of Foodgrains, Dals, Potatoes and Vegetables in Manipur

4966. SHRI N. TOMBI SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that several varieties of dal, potato, onion and other items of food-grains are imported in large quantities for consumption in Manipur;

(b) if so, the steps being taken by Government to make Manipur self-sufficient in these items: and

(c) the vegetables produced in Manipur and sold outside and the estimated amount of annual income from such sales during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : (a) to (c) . Information has been called for from the Manipur Administration and would be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

Central Assistance for Increased Production of Fruits

4967. SHRI N. S. BISHT :
SHRI G. P. YADAV :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) The production of different kinds of fruits in the country each year during the last three years;

(b) the steps taken by Government to augment the production of different varieties of fruits in the country and assistance given by the Centre of various State Governments in this regard;

(c) the main features of the schemes implemented by various State Governments in this regard State-wise; and

(d) the nature of steps proposed to be taken by the Central Government keeping in view the under-nutrition of a large number of population in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P SHINDE) (a) Production estimates are available only for banana and papaya for the last three years and are given below :

Year	Production (0'00 tonnes) Banana	Papaya
1967-68	3203.3	213.4
1968-69	3125.4	205.7
1969-70	3105.3	Yet not available.

(b) and (c) . The state Governments have taken up schemes for raising new orchards, establishment of progency-orchards-cum-nurseries, training of gardeners and rejuvenation of existing orchards through intensive cultivation. The Central Government provides technical guidance at present. There is no Central scheme for fruits production. The financial assistance to the state Government come under the block grants for the plan. Besides, the State Governments of Assam, Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Mysore, Rajasthan and Uttar Pradesh have sponsored schemes in the State sector on various fruit crops for financing from Agriculture Refinance Corporation. The Ministry has recommended to the State Governments to provide long-term loans for raising new orchards @Rs. 1,500 per acre for apples; Rs. 1.000 per acre for other hilly fruits; Rs. 3,000 per acare for grapes: Rs. 500 per acre for other fruits and

Rs. 1,000 per acre for banana and pineapple.

(d) Among the steps proposed to be taken up by the Central Government, a Centrally Sponsored Scheme for organising production and exports of fruits (banana, mango and pineapple), formulated in consultation with the concerned States, is under consideration.

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये गोबर खाद के उपयोग पर बल

4968. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिचीगन स्टेट यूनीवर्सिटी में एशिया सेन्टर के एक कृषि विशेषज्ञ ने यह कहा है कि एशियाई देशों को पश्चिमी उर्वरकों और कीटनाशी औषधियों पर विश्वास नहीं करना चाहिये तथा वे गोबर खाद पर आधारित वर्तमान कृषि प्रणाली में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त-प्रणाली से लाभ उठाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (शेर सिंह) : (क) से (ग) . मिचीगन स्टेट विश्वविद्यालय में ऐशियन सेन्टर के एक कृषि विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की सूचना सरकार को नहीं है । परन्तु यह कहा जा सकता है कि भारत में फसलों के सफल उत्पादन के लिये कार्बनिक खाद तथा रासायनिक उर्वरक दोनों के उपयोग की सिफारिश की गई हैं । यद्यपि, मृदा के भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों के सुधार पर कार्बनिक खाद का लाभदायक प्रभाव होता है, लेकिन ये कम स्तर के होते हैं, क्योंकि इन में पौध पोषकता सहज रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं । उपलब्ध कार्बनिक खाद की मात्रा भी सीमित होती हैं ।

सघन कृषि के लिये सहज रूप में उपलब्ध होने वाले पौध-खाद्य की बढ़ी मांग को पुरा करने की दृष्टि से, जबकि प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिकतम उत्पादन पर से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर जोर दिया जा रहा है, सान्द्रित तथा सहज रूप से उपलब्ध फार्म में पौध पोषक वाले उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है । भरपूर फसलों के उगाने के फलस्वरूप, जिस भूमि में पौध पोषक काफी मात्रा में समाप्त हो गये है, उसकी उत्पादकता को बनाये रखने में भी उर्वरकों का प्रयोग सहायता करता है । अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 290 लाख मीटरी टन के अतिरिक्त खाद्यान्न के उत्पादन में से लगभग 220 लाख मीटरी टन के उत्पादन का क्षेय अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के साथ उर्वरकों के बढ़ते हुये प्रयोग को है । इस प्रकार यह देखा जायेगा कि आधुनिक कृषि में उर्वरकों का प्रयोग अपरिहार्य है, जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य तथा वस्त्र की मांग को पूरा करने के लिये फसल का अधिक उत्पादन करना है ।

भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों को भूमि का आवंटन

4969. **श्री धन शाह प्रधान:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में कितने प्रतिशत भूमि-